Electronic Voting Machines

†*222. SHRI LAL K. ADVANI:*

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approved use of electronic voting machines in principle;

(b) if so, the financial commitment made for the same so far and by when the manufacturers are proposed to be given the green signal to go ahead so as to acquire in time, all the machines so required; and

(c) whether these machines are likely to reduce the expenditure on paper and stationery, the number of invalid ballot papers due to smudging, etc., the disputes about counting; the incidents of snatching or smuggling of ballot papers misappropriation of ballot papers, transport of bellot boxes for counting and damage due to booth capturing; if so, what are the facts in this regard and what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANS RAJ BHARDWAJ): (a) Yes, Sir. The Government have taken a preliminary decision to replace the ballot paper system with electronic voting machines.

(b) No such commitment has been approved so far. The placement of orders on the manufacturers will arise only after the proposal is cleared in all respects.

(c) The assessment of the Election Commission is that there are several operational, administrative and financial advantages, including these mentioned in the question; in the use of the electronic voting machines.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lal K. Advani.

SHRI LAL K. ADVANI: I have with me a question put in this House on 21st February, 1983; more than five years ago, in which the reply given by the Minister of Law to a simular question was:

"The proposal relating to introduction of electronic voting machines in elections to the House of the people and State Legislative Assemblies has been approved in principle. The Election Commission has so far tried the electronic voting machines in the field on an experimental basis in a number of constituencies."

On the same day another question was replied saying that the Election Commission has reported that "the experiment conducted so far with the use of electronic voting machines has proved a success." It is more than five years ago that the Government announced that we have accepted in principle voting machines based on the electronic technology and they have also been experimented and found to be a success. Five years after that we find the same reply given almost verbatim to this House. I regard this as a characteristic example of the Government's immobility and inertia and refusal to move an inch in so far as the electoral reforms are concerned.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI LAL K. ADVANI: Is it a fact that in 1984 when the Supreme Court declared the use of electronic voting machines as illegal, the Government took the stand that the judgement was sound, there was no need for electronic machines, and that it was wrong on the part of the Election Commission to have introduced electronic machines?

In this very House four years back, almost precisely to this date, on 9th March, 1984 I had tabled a Calling Attention Motion to which the Minister of Law at that time had replied

that the Election Commission had not been asked to introduce these machines and Government had agreed with the proposals subject to the condition that the voting machine should be used on a trial basis initially for elections in local bodies only. I pointed out that the local body elections are not under the Election Commission. How can it be that the Election Commission's decision could be subjected to being used in local bodies? The sum and substance was that the Government refused to move an inch in this direction. My question is: does the Government now propose to move an amendment to the Representation of people Act to undo the effect of the Supreme Court judgement? If so, when?

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Sir, I would like to point out to the hon. Member that right from 1982 and 1983 an experiment was made by the Election Commission in General Elections and Bye-elections regarding the use of electronic voting machines.

Sir, with regard to the Supreme Court judgement, the hon. Member knows that this was with regard to the electoral process where the use of ballot papers instead of machines was provided in the rules. So, the Sureme Court struck down in that famous case of Siven Pillai. After that we had again taken up the case of use of electronic machines with the Government and the Government in principle had approved the proposal on 7-10-1986 and voting machines are going to be introduced. Thereafter, Sir, it is not correct as what the hon. Member says we sat idle on this issue. We have pursued this issue vigorously with the Ministry of Finance and various public undertakings who are going to supply these machines. Out of the whole lot of the country, we require 5 lakh machines. They require Rs. 2250 crores of financial commitment and that is a commitment which should not be taken lightly and we are vigorously pursuing it.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि जो एक लाइन का एमेंडमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट निर्णय के प्रभाव को निरस्त करने के लिए, उसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है कि नहीं? उसमें तो एक पाई भी नहीं लगेगी। सभापति महोदय, इस मामले में इलेक्शन कमीशन की रिकमंडेशन है, सब पोलिटिकल पार्टीज की रिकमंडेशन है और सरकार को भी मंजूर है तो क्या बात है, इसका उत्तर नहीं मिला?

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान् जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पता नहीं इनको क्या गलतफहमी है। वह हो जाएगा और यह हो रहा है।

श्री राम अवधेश सिंह : कब तक होगा? टाइम बाउंड बोलिए।

श्री हंस राज भारद्वाज : वह आपकी समझ में नहीं आ सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मंत्री जी स्वयं कर रहे हैं कि हमने सन् 86 में फैसला किया है और वे अब 88 के मध्य में बोल रहे हैं, उसके बाद भी यह संशोधन वे कब लाएंगे इसके बारे में आश्वासन देने को तैयार नहीं है।

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान् जी, मैंने अर्ज किया कि यह हमारा एमेंडमेंट बिल्कुल तैयार है। हम चाहते हैं कि ... **(व्यवधान)**...

श्री राम अवधेश सिंह : टाइम तो बोलिए।

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान् जी इन पर भी टाइम बैन लगाइए। श्रीमान् मैं बड़े अदब से कह रहा हूं कि जब सरकार ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बारे में सैद्धांतिक रूप से फैसला कर लिया है कि लगाना है तो इनको यह भी समझ में आना चाहिए कि वह कानून के एमेंडमेंट के बगैर नहीं हो

सकता और वह कानून का अमेंडमेंट भी जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हमारे पास तैयार है। हम यह चाहते हैं कि अगर यह कमिटमेंट आ जाए कि पूरे देश में वोटिंग मशीन लगा सकते हैं और वह वोटिंग मशीन मिल सकती है, पूरा पैसा मिल सकता है तो कानून में एमेंडमेंट जब चाहे किया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि एक लाइन का एमेंडमेंट है, यह बात नहीं है। इसमें वोटिंग रूल्स में, रजिस्ट्रेशन आफ वोटर्स में वह लाना पड़ेगा। तो वह सारा तैयार है हमारे पास।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमन्, बी. ई. एल. और इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया से इस संबंध में पत्र व्यवहार हुआ है कि 5 लाख वोटिंग मशीने हमें चाहिए, तो उनको सप्लाई करने में कितना समय लगेगा? क्या लोकसभा के चुनावों तक यह व्यवस्था पूरी हो जाएगी जिसमें कानून का संशोधन, फाइनेंस की सेक्शन और ई.सी.आई.एल. व जो भी संबंधित संस्थाएं हैं, उनके द्वारा मशीन निर्माण आदि है? इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्री सभापति : ढाई सौ करोड़ रुपया लगेगा, अभी उन्होंने बताया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पिछली बार 165 करोड़ कहा था, उसे भी स्वीकृत किया था सरकार ने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, लोकतंत्र कोई सस्ती चीज नहीं है, लोकतंत्र बड़ा महंगा है।

श्री हंस राज भारद्वाज : जो फिगर्स माननीय सदस्य ने मांगी है, मैं उनको साफ तौर पर बता दूं कि दो पब्लिक अंडरटेकिंग्स से हमारी बात चली। इन दोनों पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जो शैड्यूल सप्लाई का है उसमें उन्होंने कहा है कि जून तक हम दो लाख मशीनें दे सकते हैं और जुलाई और अगस्त में 40-40 हजार महीने देकर इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कब ये मशीनें चाहता है, पहले इसके लिए पैसा होगा तो मशीनें मिल जाएंगी। अगर आज की जो सूखे की स्थिति है उसमें पैसा नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री अश्विनी कुमार : श्रीमन्, सरकार ने स्वीकार किया है कि वोटिंग मशीनें लगा देने से चुनावों में सुविधा होगी। बिहार में भी इसका परीक्षण हुआ था और चंडी जहां पर हर बार बूथ कैप्चर होते थे, वहां जब वोटिंग मशीन लगाई गई तो न तो बूथ कैप्चर हुए, न ही गणना या काउंटिंग में कठिनाई आई, न उसमें कोई झगड़ा हुआ। हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं कि यह केवल पैसे का प्रश्न है, साधनों का प्रश्न है, तो मैं आपसे सुरक्षा चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठे हैं और वोटिंग देश के जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंश है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सदन को आश्वासन दे सकें तो सदन को उससे लाभ होगा। मैं उसी आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री सभापति : पर आप तो जानते हैं कि किसी और मंत्री के मौजूद होने का मतलब यह तो नहीं है कि वे आपके प्रश्न के लिए तैयार होकर आएं। आपका सवाल कहने के लिए सही है, लेकिन जो प्रोसीजर है, उसको आप जानते हैं।

श्री अश्विनी कुमार : सरकार अगर बता दे तो अच्छा होगा, मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं। मेरा आपसे और प्रधानमंत्री से निवेदन करने का अधिकार है, यह तो आप मानेंगे?

श्री सभापति : आपका प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न विधि मंत्री से संबंधित है, आप उनसे प्रश्न करिए।

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमन्, मेरा ख्याल है कि मैं जब जवाब देता हूं तो माननीय सदस्य सुनते हैं। मैंने अभी सरकार के निर्णय के बारे में बताया, जिसके प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, और कहा कि 7 अक्तूबर 1986 को प्रधान मंत्री के आशीर्वाद से जो निर्णय लिया गया था, वह प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए ही लिया गया था कि हम वोटिंग मशीनों को लगाएंगे । यह निर्णय इनका थोड़े ही है, यह तो हमारा ही निर्णय है।

SHRI KAPIL VERMA: Mr. Chairman, Sir, booth capturing is a big problem. I would like to know whether a device could be built into the machine to ensure that the pace of voting does not exceed say 8 votes per minute.

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Sir, this is a device which will be there.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Sir, the introduction of voting machines will be much helpful to the Government to reduce the cost of elections. It has been estimated earlier that in every Parliamentary constituency it will save at the rate of Rs. 3.65 lakhs. This was the estimate in 1980. The total saving estimated earlier was Rs. 20 crores. In view of these benefits, why does the Government take much time to introduce these machines? Point No. 2 is, in 1984, in *Jose* v. *Sivan Pillai;* the Supreme Court declared that ballot does not include voting by the use of voting machine. Now, an amendment is necessary in respect of the definition of voting. Will the Government come forward to make the amendment to remove the defect for introduction of the machines?

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: I very humbly submit that the moment I am assured of the supply and financial commitment, the amendment is ready.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: It is saving on expenditure, Sir. It has been already calculated by the Government itself.

SHRI LAL K. ADVANI: The question is, this does not entail any financial commitment. It will reduce the expenditure. And this is according to the Government itself. I have with me the reply given to that.

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: The expenditure will be reduced in phases. There are other benefits also. If you want I can give. We are very keen. I do not think anybody reflects a better desire than the Government does in this matter. The Government has said, "We are going to do it." If there was a Supreme Court decision in 1984, the process of introduction was stopped then. The law will be amended. Suppose today you amend the law and the voting machines are not supplied. Then you cannot hold the elections. There are other processes also. They will be done simultaneously.

श्री शान्ति त्यागी : यह आप सबको मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दल, एक समुदाय ऐसा है जो बथ कैप्चर करता है और गरीबों को, हरिजनों को खासतौर से कभी मतदान करने का मौका नहीं देता । उनको उन्हीं के घरों पर रोक दिया जाता है । यह भी बता देना चाहता हूं कि ये हरिजन और गरीब लोग कांग्रेस के पक्ष के मतदाता होते हैं और इन्हीं को रोका जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोनिक डिवाइस वोटिंग मशीन है यह क्या गरीब और हरिजनों को उस को मोबाइल बना कर हरिजन मौहल्लों में वोट डलवाने का काम करेगी ? मेरा यही एक प्रश्न है ।

श्री हंस राज भारद्वाज : यह वोटिंग मशीन खुद एक हलकी और मोबाइल है इसलिये यह मोबाइल पोलिंग बथ का काम करती है । जहां तक हरिजनों को और गरीबों को वोट न डालने दन की बा . दुनिया को मालूम है कि कौन वे लोग हैं ज

हरिजनों को वोट नहीं डालने देते । लेकिन इसका इलाज वोटिंग मशीन नहीं है बल्कि पालिटिकल पार्टीज में सुधार लाने की बात है ।

SHRI PARVATHANENI UEPNDRA: The introduction of the electronic voting machines is closely interlinked with the overall electoral reforms which the Government has been promising and which we have been dmanding repeatedly. The Prime Minister also during his earlier statements, has promised that he would consult all the parties and the Election Commission and try to bring about the electoral reforms. Would the Government assure that these electoral reforms would be introduced as early as possible before the next elections?

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Surely we have the commitment to discuss with them provided they are a little free from their other activities.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: I do not hear.

MR. CHAIRMAN: You have understood. *(Interruption)* That is all left to your imagination.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, यह मजाक का मामला नहीं है ।

श्री हंसराज भारद्वाज : यह हम बता देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम अभी बात करने के लिये तैयार हैं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ कांसेन्शस है, आल पार्टीज एग्री हैं । **(व्यवधान)**

SHRI V. GOPALSAMY: The Prime Minister can convene an all-party meeting. That is the question. *(Interruptions)* He has totally stopped meeting the Opposition.

SHRI A. G. KULKARNI: Mr. Chairman, Sir, if I am right this machine was first tried in Kerala. Based on that all these programmes and plans have been made. Has the Government taken any decision to experiment or try this machine in Haryana U.P. and Bihar where the basic malady lies, that is musclemen capturing booths? Is there any possiblity of doing so? I want to now whether this machine has got any device to stop those musclemen. If not, it is no use bringing in these machines because it is in the northern States...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह क्या नये कानून मंत्री से पूंछ रहे हैं ?

SHRI A. G. KULKARNI: कानून मंत्री से ही पूंछ रहा हूं You only give lectures outside at Boat Club but we have to find a way out....

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: While speaking about musclemen he has pointed to the right side.

SHRI A. G. KULKARNI: My basic question is whether the Minister has taken cognizance of the conditions prevailing in the northern States, because the southern States are disciplined Sates. What about the northern States?

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: The experiment of the voting machine was actually started from Kerala in 1982. It was followed in Nagaland, Andhra Pradesh, Karnataka, Tripura, Delhi, Arunachal and Bihar, and this was found very satisfactory...

SHRI A. G. KULKARNI: In Bihar also?

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Yes, in Bihar also; it was in June 1983. Now, with regard to the success of the voting machine, there are several advantages of using the machine. But we are keenly awaiting the commitments of the....

SHRI A. G. KULKARNI: What about the musclemen?

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: About musclemen there is no answer available with the Law Ministry.